सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

www.hellosarkar.com

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोन: 0141-2202717
मो: 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-23 | अंक-257 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, गुरूवार 22 मई , 2025 | पृष्ठ-4 | मूल्य: 2.50

प्रधानमंत्री आज रहेंगे बीकानेर दौरे पर

26 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास-लोकार्पण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरूवार को बीकानेर से 26 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही, प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे तथा बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री देशनोक स्थित विश्वप्रसिद्ध करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी बीकानेर में उनके साथ उपस्थित रहेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशभर में सांस्कृतिक विरासत, दिव्यांगजन केंद्रित सुविधाएं और यात्रियों की सुगमता के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री द्वारा 1100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुनर्विकसित 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा जिसमें राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन (फतेहपुर शेखावाटी, देशनोक, बूंदी, मांडलगढ़, गोगामेड़ी, राजगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर-महुआ रोड) शामिल हैं। देशनोक रेलवे स्टेशन में मंदिर वास्तुकला, मेहराब और

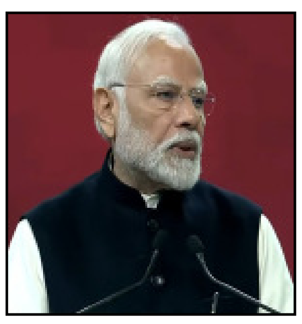

स्तंभ विषयवस्तु शैली उपयोग में ली गई है जिससे क्षेत्रीय वास्तुकला को बढ़ावा मिलेगा।

रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी ढांचा किया जा रहा सुदृढ़

भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की ओर अग्रसर है जिससे रेलवे संचालन अधिक कुशल तथा पर्यावरण अनुकूल बन रहा है। इसी क्रम में श्री मोदी चूरू-सादुलपुर रेल लाइन (58 किमी) की आधारशिला रखेंगे तथा सूरतगढ़-फलोदी (336 किमी), फुलेरा-डेगाना (109 किमी), उदयपुर-हिम्मतनगर (210 किमी), फलोदी-जैसलमेर (157 किमी) तथा समदड़ी-बाड़मेर (129 किमी) रेल लाइन विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

मजबूत सड़क तंत्र से सुरक्षा बलों को आवाजाही में होगी सुगमता

प्रधानमंत्री सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए पुष्कर में एनएच-58 पर 3 वाहन अंडरपास के निर्माण तथा एनएच-11, एनएच-70 (जैसलमेर से म्याजलार) की सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की आधारशिला रखेंगे। साथ ही, राजस्थान में लगभग 4 हजार 850 करोड़ की 7 सड़क परियोजनाओं को भी समर्पित करेंगे। इनसे आवागमन सुगम हो सकेगा। साथ ही, इन राजमार्गों के भारत-पाक सीमा तक फैले होने के कारण सुरक्षा बलों के लिए आवाजाही में सुगमता बढ़ेगी और भारत का रक्षा बुनियादी ढांचा भी मजबूत होगा।

सभी के लिए बिजली और स्वच्छ ऊर्जा हमारा विजन

केन्द्र सरकार सभी के लिए बिजली और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करवाने के विजन के साथ निरंतर काम कर रही है। इसी कड़ी में मोदी विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे जिनमें नीपको 300 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजना (बीकानेर), एसजेवीएन 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना (नावा), डीडवाना तथा कुचामन की सौर परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही, पार्ट बी पावरग्रिड सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड और पार्ट ई पावरग्रिड मेवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड के विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का शिलान्यास भी किया जाएगा।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 3 विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, जिनमें पावर ग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड तथा बीकानेर कॉम्प्लेक्स की विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली शामिल है। साथ ही, फतेहगढ़-द्वितीय विद्युत स्टेशन में परिवर्तन क्षमता के विस्तार का उद्घाटन भी किया जाएगा इससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री प्रदेश में कलासर सौर ऊर्जा परियोजना (500 मेगावाट) की आधारशिला रखेंगे और शिंभू का भुर्ज सौर ऊर्जा परियोजना (300 मेगावाट) का उद्घाटन करेंगे। इनमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित सौर पीवी मॉड्यूलों के उपयोग से 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।

राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम से क्षेत्रीय संपर्क को मिलेगा बढ़ावा

प्रधानमंत्री के आधारभूत अवसंरचना के सुदृढीकरण के विजन को गति देने के उद्देश्य से प्रदेश में राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके तहत श्री मोदी कार्यक्रम में 3,240 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 757 किलोमीटर की लंबाई के 12 राज्य राजमार्गों का उन्नयन और रखरखाव के लिए विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें मांगलियावास-पदुकलां (स्टेट हाइवे-102), ब्यावर-टेहला-अलनियावास (स्टेट हाइवे-59 और स्टेट हाइवे-104), दांतीवाड़ा-पीपाड़- मेड़ता सिटी (स्टेट हाइवे-21) शामिल हैं। राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम के विस्तार में गोटन-साथिन राजमार्ग के साथ 900 किलोमीटर के अतिरिक्त नए राजमार्ग शामिल किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से महत्वपूर्ण शहरों, औद्योगिक केंद्रों और राज्य की सीमाओं को जोड़ते हुए क्षेत्रीय संपर्क और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

नए नर्सिंग कॉलेजों से प्रशिक्षण सुविधाओं का होगा विस्तार

प्रधानमंत्री राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर में नए नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। इस पहल से स्वास्थ्य अवसंरचना, नर्सिंग शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि होगी। साथ ही, प्रधानमंत्री 132 केवी जीएसएस राजपुरा (बीकानेर) और 132 केवी जीएसएस सरदा (उदयपुर) की विद्युत अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। ये सबस्टेशन पारेषण क्षमता को बढ़ाएंगे, स्थानीय लोगों और उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाली और निर्बाध बिजली आपूर्ति भी प्रदान करेंगे।

अमृत 2.0 से शहरी क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल होगा उपलब्ध

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी झुंझुनू जिले के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस शमन परियोजना, अमृत 2.0 के तहत पाली जिले के 7 शहरों के लिए शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के पुनर्गठन सहित विभिन्न जल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इससे ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से फ्लोरोसिस प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। जल अवसंरचना परियोजनाएँ आईजीएनपी के तहत जल वितरिकाओं के पुनर्वास से सिंचाई प्रणाली की दक्षता बढ़ेगी तथा कृषि उत्पादकता एवं किसानों की आय में वृद्धि होगी।

इन विकास परियोजनाओं से देशभर में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और पेयजल सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं में समावेशी विकास सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही, विकसित भारत-विकसित राजस्थान का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

दौसा में देशभक्ति की लहर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उमड़ा जनसैलाब, निकाली गई 501 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा

दौसा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में दौसा शहर के हजारों लोग आज तिरंगा यात्रा में उमड़ पड़े। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा समिति के आव्हान पर आयोजित तिरंगा यात्रा को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने रवाना किया। तिरंगा यात्रा सहजनाथ महादेव मंदिर से लालसोट रोड होते हुए गांधी तिराहा पहुंची।

इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर, तिरंगा यात्रा प्रदेश संयोजक भूपेंद्र सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ प्रभु दयाल शर्मा, तिरंगा यात्रा जिला संयोजक राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, विधायक रामविलास मीणा, भागचंद सैनी विक्रम बंसीवाल, राजेंद्र मीणा, कन्हैयालाल मीणा, प्रेम सिंह बनवास संभाग प्रभारी तिरंगा यात्रा, जगमोहन मीणा भाजपा प्रत्याशी मौजूद रहे। कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ प्रभारी ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय सेना

ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकी ठिकानों को तो बर्बाद किया ही साथ ही दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी के साथ पूरे विश्व को अपने शौर्य और पराक्रम से यह संदेश भी दिया कि देश के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली ताकतों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

भारतीय वीर सेना के सम्मान में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्राओं को दौसा वासियों के साथ देशवासियों का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है।

तिरंगा यात्रा सहज नाथ महादेव मंदिर संस्कृत कॉलेज से रवाना हो कर लालसोट चुंगी, बरकत स्टैचू, नागौरी पुलिया, पुराना पिक्चर हॉल, रामकरण जोशी स्कूल, नेहरू गार्डन, पूनम टॉकीज होते हुए गांधी तिराहे पर पहुंची। गांधी तिराहे पर भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भारत के वीर शहीदों को नमन किया गया। इस दौरान लोग पूरे जोश और जुनून के साथ देशभक्ति गीतों की धुन पर हाथों में तिरंगा थामे वंदे मातरम, जय हिंद की सेना और भारत मां के जयकारे लगाते नजर आए। वहीं मार्ग में जगह जगह विभिन्न संगठनों एवं व्यापार मंडलों ने तिरंगा यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में महामंडलेश्वर संतोष आनंद महाराज, महंत अमर दास महाराज सहित लोगों ने तिरंगा लेकर सड़कों पर जश्न मनाया। यात्रा के दौरान 501 मीटर लंबा तिरंगा थामे शहरवासियों ने यात्रा में जोश भर दिया। वहीं भारत माता, राफेल विमान एवं समाजसेवी संस्थाओं द्वारा तैयार झांकी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। बैंड की धुनों ने लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को और अधिक प्रबल कर दिया। दुर्गा शक्ति अखाडे, खिलाडियों, होमगार्ड्स, एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड्स ने भी माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया।

तिरंगा यात्रा में टीकम सिंह गुर्जर, सत्यनारायण शाहरा, दीपक जोशी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार तिवारी, दीपक शर्मा, संतोष शर्मा, पूर्ण सैनी, राम प्रसाद गुर्जर, कंवरपाल गुर्जर, घमंडी मीणा, रामावतार कसाना, लोकेश शर्मा, नासिर खान, हाजी गुड्डू , मुरारी धौंकरिया, आदिल खान, राजेश शर्मा विनोद सांवरिया, जसवंत बेनीवाल, प्रदीप विजय सहित सैकड़ो कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में मौजूद थे।ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में शुरू हुआ 12 ट्यूबवेलों का कार्य, हर घर तक पहुंचेगा पानी

जयपुर। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं झोटवाड़ा के लोकप्रिय विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के अथक प्रयासों से झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 12 नए ट्यूबवेल का कार्य आरंभ हो चुका है। यह कार्य क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को दूर करने और जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की

दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इन नए ट्यूबवेल के निर्माण से न केवल झोटवाड़ा क्षेत्र के हजारों परिवारों को शुद्ध पेयजल सुलभ होगा, बल्कि यह आने वाले समय में जल संकट से स्थायी समाधान की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा।

कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की नीति ने राजस्थान में बुनियादी सुविधाओं को गति दी है।

राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री के विकासवादी दृष्टिकोण और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को तेजी से साकार कर रही है। झोटवाड़ा की जनता ने इस कार्य के लिए कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी का आभार जताया है।

इन ग्राम पंचायतों को मिलेगा लाभ

*करणी माता मंदिर, ग्राम-खेडी अलूफा, आईदान का बास

*कालख बांध, कालख

*हिमांशु वाटिका, निवारू

*श्री बागवाले बालाजी मंदिर, भैंसावा

*मेन स्टैंड, निकट सहकारी समिति, भोजपुरा कलां

*माचवा नंदी, माचवा

*श्री कृष्णा वाटिका के पास, मुंडियारामसर

*मेन आबादी भूमि, सरनाचौड़

*राजकीय संस्कृत विद्यालय, हाथोज

*बलाईयों की ढाणी, सांचोती, सरनाचौड़

कोटपूतली-बहरोड़ नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट को कलेक्टर ने किया एपीओ

कोटपूतली-बहरोड़। नगर परिषद कोटपूतली में तैनात आयुक्त धर्मपाल जाट को आखिरकार हटा दिया गया है। यह फैसला उनके कार्यकाल के दौरान उपजे लगातार विवादों, काम में लापरवाही, और आमजन के प्रति असम्मानजनक रवैये को लेकर लिया गया है। जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा दिनांक 20 मई 2025 को भेजी गई रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि जाट अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन निष्ठा और जिम्मेदारी से नहीं कर पा रहे थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, शहर में स्टेडियम निर्माण, अमृत योजना के तहत इटली के जोहड़ का सुदृढ़ीकरण, एसटीपी निर्माण और सीवरेज लाइन जैसे महत्वपूर्ण सिविल कार्यों में धर्मपाल जाट की कोई रुचि नहीं रही। यही नहीं, सफाई व्यवस्था तो उनकी

लापरवाही के चलते बद से बदतर हो गई, जिससे आम जनता को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ी। आयुक्त ने नगर के मास्टर प्लान को भी एक साल तक अटकाए रखा और संबंधित कंपनी पर बेवजह दबाव बनाता रहा।

धर्मपाल जाट जिला स्तर पर आयोजित होने वाली राज्य सरकार की समीक्षा बैठकों में भी उपस्थित नहीं होते थे। बिना सक्षम स्वीकृति के कार्यालय से गैरहाजिर रहना, संपर्क पोर्टल पर आए मामलों का समय पर समाधान नहीं करना उनके गैरजिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि जाट का व्यवहार आमजन से अभद्र और अपमानजनक रहा, जो उनके पद की गरिमा के सर्वथा प्रतिकूल है। कई बार शिकायतें मिलीं कि वे लोगों से बातचीत में शालीनता नहीं बरतते, जिससे जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच असंतोष बढ़ता गया।

यह पहला मौका नहीं है जब धर्मपाल जाट को पद से हटाया गया हो। इससे पहले उन्हें नागौर और किशनगढ़ से भी इसी प्रकार की शिकायतों के चलते हटाया (निलंबित) गया था। नागौर में तो स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि वे जिला कलेक्टर से भी टकराव में आ गए थे। नागौर व किशनगढ़ में भी उनका प्रशासनिक कार्यकाल विवादों से भरा रहा।

राज्य सरकार के आदेशानुसार धर्मपाल जाट को तुरंत प्रभाव से नगर परिषद कोटपूतली के आयुक्त पद से हटाकर निदेशालय में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निदेशक एवं विशिष्ट सचिव इन्द्रजीत सिंह द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जब तक नए आदेश जारी नहीं होते, तब तक जाट का मुख्यालय निदेशालय रहेगा।

पूरा थाना और 50 अन्य लोगों के खिलाफ उनके ही थाने में FIR दर्ज करने का आदेश

भरतपुर। राजस्थान के डीग जिले में गोपालगढ़ थाने के थानाधिकारी मनीष शर्मा, ASI राधाचरण सहित 7 पुलिसकर्मियों, पूरा थाना और 50 अन्य लोगों के खिलाफ उनके ही थाने में स्नद्धक्रदर्ज करने का आदेश जारी हुआ है। यह मामला साइबर ठगी की जांच के दौरान एक महिला असमीना के पति तारीफ के साथ मारपीट, घर में तोड़फोड़ और लूटपाट से जुड़ा है। दरअसल, डीग जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 ने मंगलवार को यह आदेश दिया। कोर्ट ने डीग स्क्र को मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारी से कराने और जांच फाइल कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। बुधवार को पहाड़ी ष्टश्वह्र गिर्राज प्रसाद मीणा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। बता दें, हेबतका गांव की रहने वाली असमीना ने कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उनका पति तारीफ अलवर की एक प्राइवेट कंपनी में

नौकरी करता है। वह ईद के लिए घर आया था। 11 अप्रैल को गोपालगढ़ थाने का,स्ठ्ठ राधाचरण और 5 अन्य लोग उनके घर आए। उन्होंने तारीफ को घसीटकर बाहर निकाला। जब असमीना और परिवार वालों ने उसे बचाने की कोशिश की, तो पुलिस ने पूरे परिवार की पिटाई की और तारीफ को गाड़ी में डालकर थाने ले गए। उसी दिन शाम 4 बजे थानाधिकारी मनीष शर्मा 40 लोगों के साथ असमीना के घर पहुंचे। उन्होंने असमीना के चाचा फारुख के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। जब असमीना ने रोका, तो मनीष शर्मा ने उसे भी पीटा।

वहीं, 12 अप्रैल को पुलिस ने तारीफ को थाने से रिहा किया, लेकिन तब तक उसके दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। सीकरी अस्पताल में जांच से पता चला कि उसके दोनों पैर टूट गए हैं। इसके बाद तारीफ को इलाज के लिए जयपुर ले जाया गया। असमीना ने इसकी शिकायत डीग स्क्र राजेश मीणा और ढ्ढत्र राहुल प्रकाश से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार, 30 अप्रैल को उन्होंने कामां कोर्ट में थानाधिकारी मनीष शर्मा, कांस्टेबल साहिल खान, रूपन कुमार, हेड कांस्टेबल विनोद, हितेश,,स्ठ्ठ राधाचरण, पूरे थाने के पुलिसकर्मियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ याचिका दायर की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि इस मामले में थाने के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, इसलिए जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए। अब जांच के बाद पूरी फाइल कोर्ट में पेश की जाएगी। इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसकी पूरी सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।

जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का गहराता संकट

पर्यावरण वैज्ञानिकों के मुताबिक जैव विविधता के क्षरण का सीधा असर भविष्य में कृषि, खाद्य पैदावार इत्यादि पर पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी पर जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम पर्यावरणीय संतुलन को न बिगड़ने दें। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस प्रकार जंगलों में अतिक्रमण, कटाई, बढ़ता प्रदूषण और पर्यटन के नाम पर गैर जरूरी गतिविधियों के कारण पूरी दुनिया में जैव विविधता पर संकट मंडरा रहा है, वह पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का स्पष्ट संकेत है और यदि इसमें सुधार के लिए शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में बड़े नुकसान के तौर पर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।

(लेखक - योगेश कुमार गोयल)

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (22 मई) पर विशेष)

मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी पर जैव विविधता पर गंभीर संकट मंडरा रहा है और जीव-जंतुओं, वनस्पतियों इत्यादि की अनेक प्रजातियां तेजी से लुप्त होती जा रही हैं। जीव-जंतु और वनस्पति ही धरती पर बेहतर और जरूरी पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं लेकिन प्रदूषित वातावरण और प्रकृति के बदलते मिजाज के कारण जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। अनेक शोधों से यह चिंताजनक तथ्य सामने आ चुका है कि पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र बेहद खराब हो चुका है। मानवीय दखल से दूर रहने के कारण और स्थानीय जनजातीय लोगों की भूमिका के चलते धरती का केवल तीन प्रतिशत हिस्सा ही पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित रह गया है। जैव विविधता के मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता और समझ बढ़ाने तथा धरती पर मौजूद जंतुओं और पौधों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष 22 मई को एक खास थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का इस वर्ष का विषय है 'प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास', जो न केवल पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है बल्कि जैव विविधता और सतत विकास के बीच गहरे अंतर्संबंध को भी उजागर करता है।

अमेरिका की यूनिवर्सिटी आफ एरिजोना के शोधकर्ताओं का मानना है कि अगले पांच दशकों में जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की प्रत्येक तीन में से एक यानी एक तिहाई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। शोधकर्ताओं ने दुनियाभर के छह सौ स्थानों पर पांच सौ से ज्यादा प्रजातियों पर एक दशक तक अध्ययन करने के बाद पाया कि अधिकांश स्थानों पर 44 प्रतिशत प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इस अध्ययन में विभिन्न मौसमी कारकों का अध्ययन करने के बाद शोधकर्ताओं इस नतीजे पर पहुंचे कि यदि गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो 2070 तक दुनियाभर में कई प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। ब्रिटेन स्थित 'स्मिथसोनियन एनवायरनमेंटल रिसर्च सेंटर' के मुताबिक विश्व के केवल 2.7 प्रतिशत हिस्से में ही अप्रभावित जैव विविधता बची है, जो बिल्कुल वैसी ही है, जैसी पांच सौ वर्ष पूर्व हुआ करती थी। इन क्षेत्रों में सदियों पहले जो पेड़-पौधे और जीव पाए जाते थे, वे प्रजातियां आज भी मौजूद हैं। जो अप्रभावित जैव विविधता वाला क्षेत्र बचा है, वह भी जिन-जिन देशों की सीमाओं के अंतर्गत आता है, उनमें से केवल 11 प्रतिशत क्षेत्र को ही संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अप्रभावित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से अधिकांश इलाके उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, जहां मानव उपस्थिति कम रही है, लेकिन अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ये जैव विविधता से समृद्ध नहीं थे। 'इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर' (आइयूसीएन) एक रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में वन्यजीवों और वनस्पतियों की हजारों प्रजातियां संकट में हैं और आने वाले समय में इनके विलुप्त होने की संख्या तथा दर में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। आइयूसीएन ने करीब एक लाख पैंतीस हजार प्रजातियों का आकलन करने के बाद इनमें से सैंतीस हजार चार सौ प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर मानते हुए खतरे की सूची में शामिल किया था। आइयूसीएन के अनुसार नौ सौ से ज्यादा जैव प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और 37 हजार से ज्यादा प्रजातियों पर विलुप्त होने का संकट मंडरा रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक वन्यजीवों की तस्करी भी दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरी है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक तस्करी स्तनधारी जीवों की होती है। वन्यजीव तस्करी में 22 प्रतिशत तस्करी के मामले रेंगने वाले जीवों के और 10 प्रतिशत पक्षियों के होते हैं जबकि पेड़-पौधों की तस्करी का हिस्सा 14.3 फीसद है।

'स्टेट ऑफ वर्ल्ड बर्ड्स' नामक एक रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आ चुका है कि दुनिया में पक्षियों की करीब 39 प्रतिशत प्रजातियों की संख्या स्थायी है और मात्र 6 प्रतिशत प्रजातियां ही ऐसी हैं, जिनकी संख्या बढ़ रही है, जबकि 48 प्रतिशत प्रजातियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पक्षियों की प्रजातियों की संख्या में गिरावट को भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जहां 14 प्रतिशत प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं केवल 6 प्रतिशत प्रजातियों की संख्या ही स्थिर है जबकि 80 प्रतिशत प्रजातियां कम हुई हैं। इनमें से 50 प्रतिशत प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट और 30 प्रतिशत प्रजातियों में कम गिरावट दर्ज की गई है। सालाना पक्षी गणना में अब प्रतिवर्ष पक्षियों की संख्या और विविधता में गिरावट आ रही है, जिसका बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और जंगलों का कटना है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पक्षियों पर हुए शोध के नतीजे भी चौंकाने वाले हैं। वहां वन क्षेत्रों में मानवीय दखल, वनों की कटाई और तेजी से बढ़ते प्रदूषण के कारण पक्षियों की संख्या में 60-80 प्रतिशत तक की कमी आई है।

पर्यावरण वैज्ञानिकों के मुताबिक जैव विविधता के क्षरण का सीधा असर भविष्य में कृषि, खाद्य पैदावार इत्यादि पर पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी पर जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम पर्यावरणीय संतुलन को न बिगड़ने दें। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस प्रकार जंगलों में अतिक्रमण, कटाई, बढ़ता प्रदूषण और पर्यटन के नाम पर गैर जरूरी गतिविधियों के कारण पूरी दुनिया में जैव विविधता पर संकट मंडरा रहा है, वह पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का स्पष्ट संकेत है और यदि इसमें सुधार के लिए शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में बड़े नुकसान के तौर पर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। विकास के नाम पर यदि वनों की कटाई बदस्तूर जारी रही और जीव-जंतुओं तथा पक्षियों से उनके आवास छीने जाते रहे तो ये प्रजातियां धरती से एक-एक कर लुप्त होती जाएंगी और भविष्य में इससे पैदा होने वाली भयावह समस्याओं और खतरों का सामना समस्त मानव जाति को ही करना होगा।

बहरहाल, शोधकर्ताओं का पृथ्वी पर जैव विविध अस्तित्व पर मंडराते संकट को लेकर कहना है अधिकांश प्रजातियां मानव शिकार के कारण लुप्त ह जबकि कुछ अन्य कारणों में दूसरे जानवरों का ह और बीमारियां शामिल हैं। हालांकि उपग्रहों से तस्वीरों के आधार पर शोधकर्ताओं का मानना है धरती के ऐसे बीस फीसद हिस्से की जैव विविधत बचाया जा सकता है, जहां अभी पांच या उससे कम जानवर ही गायब हुए हैं लेकिन इसके लिए मानव प्र से अछूते क्षेत्रों में कुछ प्रजातियों की बसावट ब होगी ताकि पारिस्थितिकीय तंत्र में असंतुलन पैदा न जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही गर्मी से भी विविधता खतरे में पड़ी है। जैव विविधता पर संकट इसी प्रकार मंडराता रहा तो धरती से प्राणी जगत खात्मा होने में सैकड़ों साल नहीं लगने वाले।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, पर्यावरण मामलो जानकार और 'प्रदूषण मुक्त सांसें' पुस्तक के ले हैं) (यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इ संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

भीतर के दुश्मन

किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात में है कि वहां सभी तरह की वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। बशर्ते अभिव्यक्ति समाज में विभाजन की कारक और राष्ट्र के हितों के विरुद्ध न हो। हरियाणा में अशोका विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की सोशल मीडिया पोस्ट पर उठे विवाद के बाद की गई गिरफ्तारी ने कई सवालों को जन्म दिया है। दरअसल, प्रोफेसर अली खान ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के कुछ पहलुओं को लेकर सवाल उठाए थे। यह घटनाक्रम हमें याद दिलाता है कि देश में असहमति के विचारों को कैसे देश के विरुद्ध दर्शाया जा रहा है। हरियाणा पुलिस ने अपनी कार्रवाई के पक्ष में दलील दी है कि प्रोफेसर की टिप्पणी भारत की एकता को खतरे में डालने वाली है। निस्संदेह, यह घटना विचार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को संदिग्ध रूप में दर्शाने का उपक्रम नजर आता है। यह स्पष्ट है कि प्रोफेसर महमूदाबाद की आवाज कोई सतही टिप्पणी नहीं है। वे एक सम्मानित अकादमिक और सार्वजनिक विमर्श में सक्रिय रहने वाले बुद्धिजीवी हैं। जिन्हें भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने के साथ विचारशील जुड़ाव के लिये जाना जाता है। उनकी टिप्पणी भले ही कितनी भी आलोचनात्मक क्यों न हो, उसे राष्ट्रीय एकता के लिये खतरे के रूप में चित्रित करना एक अतिशयोक्ति ही कही जाएगी। निश्चित रूप से इस मामले में पुलिस की कार्रवाई एक ऐसी अस्वीकार्य मिसाल है, जो कालांतर लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का अतिक्रमण ही करती है। प्राचीन काल से ही हमारे विश्वविद्यालय रचनात्मक बहस के लिये उपयुक्त स्थान के रूप में जाने जाते रहे हैं। जहां राज्य की निगरानी के जरिये हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होती थी। सवाल इस घटनाक्रम के समय व संदर्भ को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से 'ऑपरेशन सिंदूर', एक ऐसा सैन्य अभियान था, जिसे व्यापक सार्वजनिक जनसमर्थन और मीडिया कवरेज मिली। सही मायने में एक परिपक्व लोकतंत्र में किसी भी आलोचना को सहज भाव से लिया जाना चाहिए। निस्संदेह, स्वतंत्र वैचारिक अभिव्यक्ति पर सवाल खड़े करना और उसे दंडात्मक कार्रवाई के जरिये दबाने का प्रयास अस्वीकार्य ही है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि अकादमिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी किसी सत्ताधारी व्यवस्था की मर्जी से दिए गए विशेषाधिकार नहीं है, ये संवैधानिक गारंटी हैं। यह सुखद ही है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने प्रोफेसर महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई करने के लिये सहमति दे दी है। जो इस मामले में एक उम्मीद की किरण कही जा सकती है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में अपमान के बाद राहत के लिये कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जूझना व्यक्ति के लिये कष्टदायक ही है। यह सही समय है कि हमारी संस्थाएं देशभक्ति को अंध आज्ञाकारिता के रूप में परिभाषित न करें। सही मायनों में सच्ची देशभक्ति सवाल करने, विचार करने और यहां तक कि असहमति जताने की क्षमता में निहित है। जिसको लेकर सलाखों के पीछे डालने का भय नहीं होना चाहिए। सही मायनों में एक ट्वीट पर एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा नहीं करती बल्कि यह केवल राष्ट्रीय असुरक्षा को ही उजागर करती है। यही वजह है कि देश की कई चर्चित हस्तियों व राजनेताओं ने प्रोफेसर अली के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने उन आक्षेपों को खारिज किया है जिनमें उनकी पोस्ट को महिला विरोधी और धार्मिक द्वेष फैलाने वाला बताया गया। उन्होंने सवाल उठाये हैं कि उनकी टिप्पणी कैसे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिये चुनौती है।

एक कप चाय कितना महत्वपूर्ण

(लेखक - संजय गोस्वामी)

21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर विशेष)

हर वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल एक पेय पदार्थ को समर्पित नहीं है, बल्कि यह किसानों, उद्यमियों, चाय उत्पादकों और उद्यमियों की एक साझा कहानी को सम्मान देने का अवसर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन की शुरुआत 2020 में की गई थी, ताकि चाय उद्योग में काम करने वाले ताइवान की मेहनत, चाय की खेती से जुड़ी स्थिरता, और चाय के वैश्विक सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व को प्रमुखता दी जा सके। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और असम, दार्जिलिंग, नीलगिरि जैसी चायों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। चाय सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि रिश्ते को जोड़ने वाला माध्यम है। किसी भी अनन से भी एक कप चाय साझा करते हुए ही एक अपनापन पठने लगता है। आज जब पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन, खेती के संकट, और उपभोक्ता अशिक्षा से यात्रा कर रहे हैं, चाय दिवस हमें यह सलाहकार पर मजबूर करता है कि हम जिन छात्रों का आनंद लेते हैं, उनके पीछे किसकी मेहनत और विद्वतता जुड़ी हुई है। चाय हमारे जीवन का सिद्धांत भाग है। आज के दौर में चाय से लेकर महान मेहमान तक और क्या हो सकता है! चाय एक लोकप्रिय पेय है जिसे दुनिया भर में कई लोग पसंद करते हैं। चाय के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे ग्रीन टी, ब्लैक टी, और प्लांट चाय, और इसे कई तरह से बनाया जा सकता है। चाय के कई प्रकार स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। चाय वजन कम करने के लिए-चाय वजन कम करने के नियम-खाली पेट चाय न पिएं इससे एसिडिटी हो सकती है।चाय के साथ हैवी एसिडिटी हो सकती है।चाय के साथ भारी मात्रा में चीनी न खाएं- इससे वजन कम हो सकता है। अपने देश में एक एवरेज एडल्ट रोज क्लोज 3 कप चाय पीता है। एक कप सुबह-सुबह ही, दूसरे के साथ और तीसरे तीन या शाम को। घरों में ज्यादातर चाय-दूध, चीनी और चायपत्ती के साथ बनाया जाता है, जिसे स्टॉककर तैयार किया जाता है। एक कप (250 ग्राम) दूध वाली चाय में लगभग 10 ग्राम चीनी, 50 से 60 कोलोहाइड्रा कैफीन और लगभग 2 ग्राम दूध से भरपूर हो सकती है। अगर आप एक दिन में 3 कप चाय पीते हैं, तो आप रोजाना करीब 30 ग्राम चीनी, 6 ग्राम चाय और 150 कोल्ड कैफीन का सेवन कर रहे हैं। आपके देश में एक एवरेज एडल्ट रोज करीब 3 कप चाय पीता है। एक कप सुबह-सुबह ही, दूसरे के साथ और तीसरे तीन या शाम को। घरों में ज्यादातर चाय-दूध, चीनी और चायपत्ती के साथ बनाया जाता है, जिसे स्टॉककर तैयार किया जाता है। एक कप (250 ग्राम) दूध वाली चाय में लगभग 10 ग्राम च 50 से 60 कोलोहाइड्रा कैफीन और लगभग 2 ग्राम दू भरपूर हो सकती है। अगर आप एक दिन में 3 कप चाय हैं, तो आप रोजाना लगभग 30 ग्राम चीनी, 6 ग्राम कैफीन 150 कोल्ड कैफीन का सेवन कर रहे हैं।चाय कई बीमारि कम जोखिम से भी जुड़ी है, जिसमें संज्ञानात्मक समस हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और बहुत कुछ शामिल है। ले चाय में कई अन्य पोषक तत्व और खनिज हो सकते हैं जि बारे में आप नहीं जानते होंगे, जो आपके स्वास्थ्य के वि पहलुओं में महत्वरखता है हैं।

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

(चिंतन- मनन)

कौन बने राजा

भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को पक्षियों का राजा माना गया है लेकिन वे अपने स्वामी की सेवा में इतना व्यस्त रहते थे कि उन्हें पक्षियों का हालचाल जानने का समय ही नहीं मिल पाता था। एक दिन पक्षियों ने अपनी सभा बुलाई और इस बात पर विचार-विमर्श किया कि ऐसे राजा का क्या लाभ, जो कभी हमें देखने तक नहीं आता।

सभी ने काफी सोच-विचार कर उल्लू को राजा घोषित कर दिया। उल्लू के राजतिलक की तैयारी होने लगी, तभी एक कोने में बैठे कौवे ने चिल्लाते हुए कहा कि यह फैसला हमें मंजूर नहीं है। राजा गरुड़ को भले ही हमारे पास आने का समय न मिलता हो, लेकिन जब भी मौका मिलेगा वह अवश्य आएंगे। मगर उल्लू को राजा बनाने का क्या लाभ, जिसे दिन में दिखाई ही नहीं पड़ता।

वह हमारी परेशानियों को कैसे हल करेगा। वह दूसरों की बातें सुनकर फैसला करेगा जिसका परिणाम यह होगा कि चाटुकारों का बोलबाला हो जाएगा। किसी ने तर्प दिया कि उल्लू रात में देख सकते हैं इसलिए वह रात में हमारी समस्या सुलझा देंगे। कौवे ने कहा- ऐसा राजा मुझे मंजूर नहीं रात में आकर हमारी नींद हराम करे। फिर हम प रात में ठीक से देख नहीं पाते। हम पहचानेंगे वै कि उल्लू ही आया है।

इस बात का लाभ उठाकर कोई राक्षस उस जगह आ सकता है और हमें मारकर खा सकता पक्षियों ने मान लिया कि राजा ऐसा होना चाहि जिसे प्रजा के दुख-दर्द दिखाई तो पड़ें। अंत गरुड़ को ही राजा बनाए रखने का फैसला वि गया।

विचार मंथन

जज भी कॉलेजियम से प्रताड़ित?

(लेखक - सनत जैन)

हाल ही में इंदौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की विदाई के अवसर पर जस्टिस रमना की भावुक प्रतिक्रिया ने न्यायपालिका की कॉलेजियम को लेकर एक बड़े सवाल को जन्म दे दिया है। क्या ईमानदार और निष्पक्ष न्यायाधीश कॉलेजियम प्रणाली की आंतरिक राजनीति और न्यायपालिका के सत्ता संघर्ष का शिकार हो रहे हैं? दरअसल जस्टिस रमना ने विदाई समारोह में कहा, कि जब उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थीं। तब उन्हें आंध्रा से मध्य प्रदेश स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह तबादला वरिष्ठताक्रम एवं तंग करने के उद्देश्य से किया गया था। एक वरिष्ठ न्यायाधीश की ओर से कॉलेजियम के लिए इस तरह की प्रतिक्रिया आना केवल व्यक्तिगत पीड़ा का प्रकटीकरण नहीं हो सकता है, बल्कि यह न्यायिक व्यवस्था की आंतरिक कार्यप्रणाली की सियासत को भी उजागर करता है। कॉलेजियम प्रणाली का उद्देश्य न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखना है। हाल के वर्षों में कॉलेजियम की व्यवस्था विवादों में घिरी है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की वरिष्ठता मे अनदेखी, नए जजों की नियुक्ति में सरकार और कॉलेजियम के बीच का संघर्ष, ट्रांसफर और पोस्टिंग के जरिए चहेते जजों को आगे करने के लिए कॉलेजियम के साथ-साथ सरकार की पारदर्शिता एवं राजनीतिक कारणों से नए जजों की नियुक्ति में विचारधारा के आधार पर निर्णय लेने, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह जैसी शिकायतें आम हो गई हैं। जस्टिस रमना का अनुभव यह दर्शाता है, कैसे एक ईमानदार न्यायाधीश, जो अपने काम में ईमानदारी और न्यायप्रियता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जाने जाते हैं, वह कॉलेजियम और सरकार की संस्थागत राजनीति का शिकार हो रहे हैं। जिसके कारण न्यायपालिका में लगातार विश्वास की कमी पैदा हो रही है। न्यायमूर्ति रमना की यह प्रतिक्रिया न्यायिक जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करती है। एक न्यायाधीश को तंग करने अथवा उसके जायज हकों को प्रभावित करने के लिए उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। यह कृत्य न्यायपालिका की साख को नुकसान पहुंचाता है। आम नागरिकों के भरोसे को भी डगमगाता है। सरकार भी इसका फायदा उठाती है। जजों की इस लड़ाई की बंदर-बॉट में पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग में जिस तरह की ताकत दिखाना शुरू कर दी है, कॉलेजियम की अनुशंसा को नजर अंदाज करते हुए या तो जजों की नियुक्ति नहीं की है या जिन जजों की नियुक्ति सरकार ने चाही है, वह सरकार ने की है, इससे कॉलेजियम की साख में भी धब्बा लगा है।

भारत की न्यायपालिका को कॉलेजियम और जजों के काम करने के तौर तरीके को लेकर आत्म निरीक्षण की आवश्यकता है। कॉलेजियम को अपनी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ जवाबदेही को प्राथमिकता देनी होगी। न्यायाधीशों के स्थानांतरण और पदोन्नति के निर्णयों में न्यायाधीशों की आंतरिक राजनीति, अहंकार या गुटबंदी अथवा सरकार हावी हो जाएगी। इससे न्यायपालिका की संस्थागत विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुंचना तय है। अब समय आ गया है जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप स्वयं को ढालें। जब न्यायपालिका के ही जज पीड़ा और अन्याय की बात करेंगे तो सवाल उठेंगे और यह मामला किसी एक जज का नहीं है। पिछले एक दशक में कई बार जज सार्वजनिक रूप से सामने आकर कार्य प्रणाली को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन भी समय-समय पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं। यह स्थिति समूची न्यायपालिका की साख पर चोट पहुंचाने वाली है। न्यायपालिका का काम न्याय देना ही नहीं है, न्याय व्यवस्था पर अ आदमी का विश्वास भी हो, न्याय पालिका लिए यह सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहि पिछले कुछ वर्षों में एक धारणा यह भी बन लगी है, कानून के नाम पर जिस तरह से अ आदमियों को प्रताड़ित किया जा रहा है उ रोक पाने में न्याय पालिका की भूमिका देख को नहीं मिल रही है। जो कुछ वर्षों पहले त देखने को मिलती थी। न्याय पालिका अ सरकार के दबाव में काम करती हुई दिख र है। आम लोगों को न्याय पालिका से जो न्य मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। लोग व वर्षों से जेलों में बंद पड़े हुए हैं। कई वर्षों त उनकी चार्जशीट न्यायालय में पेश नहीं की रही है। इसके बाद भी न्यायालय से उ जमानत नहीं मिल रही है।

सरकारी जमीन पर किसी का हक नहीं, चाहे वह वक्फ बाय यूजर ही क्यों न हो

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन सुनवाई, केंद्र ने कहा-

नई दिल्ली।

वक्फ संशोधन एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हम एक बहुत पुरानी समस्या को खत्म कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1923 में हुई थी। उन्होंने कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता, चाहे वो वक्फ बाय यूजर के आधार पर ही क्यों न हो। अगर कोई जमीन सरकारी है, तो सरकार को पूरा अधिकार है कि वह उसे वापस ले, भले ही उसे वक्फ घोषित कर दिया गया हो।केंद्र ने यह भी कहा कि वक्फ एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है और यह कानून सिर्फ इसके प्रशासन और प्रबंधन को सुधारने के लिए लाया गया है, इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले मंगलवार को सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के सामने केंद्र ने पहले उठे मुद्दों तक सुनवाई सीमित रखने का अनुरोध किया था। सॉलिसिटर मेहता ने कहा था कि सुनवाई उन तीन मुद्दों पर हो, जिन पर जवाब दाखिल किए गए हैं। नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई कर रहा है। इसमें सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को बहस के लिए 7 घंटे का वक्त तय किया है। मंगलवार को 3 घंटे तक याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने मामला बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। सॉलिसिटर मेहता ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां मंत्रालय ने एक बिल बनाया और बिना सोच-विचार के वोटिंग कर दी गई हो। कुछ याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय की ओर से नहीं बोल सकते। आपके पास जो याचिकाएं आई हैं, वे ऐसे लोगों ने दायर की हैं जो सीधे इस कानून से प्रभावित नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसी ने यह नहीं कहा कि संसद को यह कानून बनाने का अधिकार नहीं था। जेपीसी की 96 बैठकें हुईं और हमें 97 लाख लोगों से सुझाव मिले, जिस पर बहुत सोच-समझकर काम किया गया।

बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान को बताया बिगड़ी औलाद और हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा का किया ऐलान

मुजफ्फरपुर।

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर तीखे शब्दों में पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पाकिस्तान को बिगड़ी औलाद बताते हुए कहा कि अगर वह नही सुधरा, तो भारत उसे फिर सबक सिखाएगा। यहां बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को पहले ही सीधा कर दिया है। अगर बेटों के हाथ में कमान दी गई, तो नतीजा और भी कड़ा होगा। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देश को दुनिया में अलग-थलग किया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नही आया, तो आगे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। **हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा का ऐलान** आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वह भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए 7 नवंबर से 10 दिवसीय पदयात्रा करेंगे। यह यात्रा नई दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन (131 किमी) तक जाएगी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल धर्म की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास है। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने जातिवाद की राजनीति को देश की प्रगति में बाधक बताया। उन्होंने कहा, कि जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए। जो नेता जातियों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें जनता सबक सिखाए। बाबा बागेश्वर ने बागेश्वर धाम में बन रहे कैंसर अस्पताल को लेकर कहा कि इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और 2027 में उन्हीं के हाथों इसका उद्घाटन भी होगा। बाबा ने कहा कि बागेस्वर मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं रहेगा, बल्कि गरीबों की स्वास्थ्य सेवा का भी केंद्र बनेगा। बाबा देर रात मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर के इंद्रपुरी कॉलोनी में दीनानाथ दास के निवास पर पहुंचे, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान जदयू और भाजपा नेताओं ने भी उनसे मुलाकात की।

ज्योति ने कबूला पाकिस्तानी एजेंट्स से थे संपर्क, दानिश से करती थी रोज बात

जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर से चल रही है पूछताछ

नई दिल्ली।

पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ चल रही है। ज्योति ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंट्स के साथ संपर्क होने की बात कबूली है। इतना ही नहीं उसने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी के भी संपर्क में होने की बात कही है। हालांकि इसे लेकर पुलिस की ओर से अब तक कुछ नहीं कहा गया है। पुलिस ने ज्योति को 16 मई को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ज्योति ने कबूल कर लिया है कि पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ उसके संपर्क थे। उसने यह भी कबूल किया कि वह नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश के साथ भी नियमित रूप से बातचीत करती थी। रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ के रिकॉर्ड्स से पता चला है कि ज्योति की दानिश से पहली बार मुलाकात 2023 में हुई थी। उस दौरान वह पाकिस्तान यात्रा के लिए वीजा हासिल करने के लिए पाकिस्तानी उच्चायोग गई थी। खास बात है कि पहलगाम हमले के बाद 13 मई को दानिश को भारत सरकार ने वापस जाने को कहा था। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि ज्योति ने कहा कि 2023 में वह पाकिस्तान की यात्रा के लिए वीजा की जानकारी जुटाने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग गई थी। इस दौरान उसकी मुलाकात दानिश के कॉन्टैक्ट अली हसन से हुई थी, जिसने वहां उसके रहने और यात्रा की व्यवस्था की थी। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ज्योति ने खुलासा किया है कि हसन ने उसकी दो लोगों से मुलाकात कराई थी, जो पाकिस्तान के खुफिया अधिकारी माने जा रहे हैं। ज्योति ने बताया है कि उसने शाकिर का नंबर जट रंधावा के नाम से सेव किया था, ताकि किसी को शक न हो। रिपोर्ट के मुताबिक भारत लौटने के बाद भी वह लगातार पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों के संपर्क में रही। वह उनके साथ व्हाट्सऐप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसी ऐप्स के जरिए संपर्क साधती थी।

आतंक के सामने नहीं झुकेगी भारत की आध्यात्मिक शक्ति

अमरनाथ यात्रा के लिए 3.5 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली।

पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से लोगों में डर का माहौल बना हुआ था लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से फिर से लोगों का जोश हाई है। कुछ दिन पहले पहले खबर आ रही थी कि अमरनाथ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं का मनोबल टूट गया है और वे जाने से कतरा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से रजिस्ट्रेशन के आंकड़ सामने आ रहे हैं, यह देखकर, बाकी श्रद्धालुओं में भी उत्साह दिख रहा है।

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट कर लिखा है कि आतंक के सामने नहीं झुकेगी भारत की आध्यात्मिक शक्ति। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन किया है।

वहीं, प्रशासन सभी आने वाले भक्तों और सेवा प्रदाताओं को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए आवास, बिजली, पानी, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग समन्वय में काम कर रहे हैं।

साल 2025 में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी, वहीं इसकी समाप्ति 9 अगस्त को होगी। इस पवित्र यात्रा के लिए 14 अप्रैल से ऑनलाइन मोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन

शुरू हो चुके हैं। इसके लिए तीर्थयात्री श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

अब अमेरिका में डंकी रुट से भेजने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

ट्रैवल एजेंसियां यात्रा और इमिग्रेशन के नाम पर कर रहीं लोगों का शोषण

नई दिल्ली।

अमेरिका ने अवैध इमिग्रेशन पर लगाम लगाने सख्त कदम उठाया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने भारतीय ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों, सीनियर अधिकारियों और एक्सिक्युटिव्स वीजा पर रोक लगा दी है।

इन ट्रैवल एजेंटों पर आरोप है कि इन्होंने भारतीय नागरिकों को गुमराह कर गलत और गैरकानूनी तरीकों से अमेरिका भेजने का प्रयास किया।

ये एजेंसियां यात्रा और इमिग्रेशन की मदद के नाम पर लोगों का शोषण कर रही थीं। अमेरिकी सरकार ने साफ कहा है कि जो भी लोग मजबूर या भोले-भाले लोगों को अवैध तरीके से देश में लाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन की उस मुहिम का हिस्सा है, जिसमें अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क्स को खत्म करने का प्रयस किया जा रहा है। इस कदम से यह संदेश जाता है कि अब ऐसे किसी भी गैरकानूनी काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत में स्थित और ऑपरेट करने वाली कई ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों, सीनियर अधिकारियों और टॉप मैनेजमेंट पर वीजा पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। स्टेटमेंट में कहा है कि ये ट्रैवल एजेंसियां जानबूझकर भारतीय नागरिकों को अवैध तरीके से अमेरिका भेजने में मदद कर रही थीं।

यूएस मिशन इंडिया के कांसुलर अफेयर्स और डिप्लोमैटिक सिक्योरिटी सर्विस की टीम हर दिन अमेरिकी एम्बेसी और कांसुलेट्स के ज़रिए ऐसे लोगों की पहचान कर रही है जो गैरकानूनी इमिग्रेशन, ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग जैसे मामलों में शामिल है। अमेरिका ने कहा है कि ये वीज़ा बैन सिर्फ आम वीज़ा अप्लिकेंट्स पर ही नहीं, बल्कि क्वालिफाई करने वाले लोगों पर भी लागू होगा।

यह एक ग्लोबल पॉलिसी है, यानी दुनिया के किसी भी कोने में ऐसे मामलों में लिप्त लोगों पर यह नियम लागू किया जा सकता है।

भारतीय नौसेना को मिला अनोखा प्राचीन शैली का जहाज, आज उजागर होगा नाम

नई दिल्ली।

भारतीय नौसेना को आज एक ऐतिहासिक और अद्वितीय जहाज मिलने जा रहा है, जिसका निर्माण पूरी तरह प्राचीन भारतीय तकनीकों के आधार पर किया गया है। इस तरह का जहाज न तो आधुनिक तकनीक से बना है और न ही दुनिया की किसी अन्य नौसेना के पास इसकी कोई मिसाल मौजूद है। यह विशेष जहाज पांचवीं शताब्दी ईस्वी के एक पारंपरिक भारतीय समुद्री पोत का पुनर्निर्माण है, जिसकी प्रेरणा महाराष्ट्र स्थित अजन्ता की गुफाओं में बनी एक समुद्री चित्रकला से ली गई है। इसका निर्माण कार्य केरल के पारंपरिक कारीगरों ने पूरी तरह हाथ से और प्राकृतिक सामग्रियों के उपयोग से किया है। गोवा की एमएसएमई कंपनी होडी इनोवेशंस, संस्कृति मंत्रालय, और भारतीय नौसेना के संयुक्त प्रयास से यह ऐतिहासिक प्रोजेक्ट ने साकार रुप लिया है। जहाज निर्माण की नींव 12 सितंबर 2023 को रखी गई थी और अब यह आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जा रहा है। इस जहाज का नाम केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उजागर करने वाले हैं और इसी के साथ इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा।

आधुनिक जहाजों से है अलग नेवी प्रवक्ता कैप्टन विवेक मधवाल के अनुसार, यह जहाज आधुनिक जहाजों से बिल्कुल अलग है। इसमें चौकोर पाल, लकड़ी की पतवारें और हाथ से चलाए जाने वाले चप्पू हैं। इसके निर्माण के दौरान डिज़ाइन और तकनीकी जांच के लिए आईआईटी मद्रास के समुद्री इंजीनियरिंग विभाग की सहायता ली गई। इस ऐतिहासिक जहाज का उद्देश्य सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना नहीं है, बल्कि यह भारत की प्राचीन समुद्री शक्ति और व्यापारिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना है। जहाज की पहली समुद्री यात्रा गुजरात से ओमान तक की जाएगी, जिसमें सदियों पुराने समुद्री व्यापार मार्ग का अनुसरण किया जाएगा।

यदि कर रहे अमेरिका जाने का प्लान....ट्रंप सरकार की नई नीति को पढ़ लें

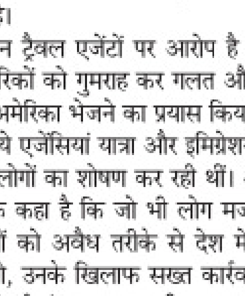

नई दिल्ली।

भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक अहम और महत्वपूर्ण चेतावनी दी है। अगर भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं, तब उन्हें नए नियमों को जानना जरुरी है। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास और दिल्ली स्थित भारतीय दूतावास दोनों ने साफ किया है। इस महीने में अब तक भारत में अमेरिकी दूतावास द्वारा अवैध आव्रजन के बारे में किया गया यह तीसरा पोस्ट है। यह स्पष्ट नहीं है कि इन विशेष और लगातार चेतावनी संदेशों के पीछे क्या कारण है।

अमेरिका में ट्रम्प सरकार के तहत एक नए नीतिगत परिवर्तन के तहत, अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर निर्वासन हो सकता है, बल्कि वीजा रद्द होने और अन्य कई परेशानियां भी हो सकती हैं। अमेरिकी दूतावास की ताजा चेतावनी इस प्रकार है कि यदि आप अपनी अधिकृत अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहते हैं, तब आपको निर्वासित कर सकते है। इतना ही नहीं भविष्य में अमेरिका की यात्रा पर स्थायी प्रतिबंध लग सकता है। इस माह की शुरुआत में भारत स्थित अमेरिकी दूतावास के एक अन्य संबंधित पोस्ट में कहा गया था, अमेरिकी सरकार ने धोखाधड़ी से निपटने और अवैध आव्रजन को समाप्त करने के लिए एक समन्वित अंतर-एजेंसी प्रयास शुरू किया है। वीज़ा धोखाधड़ी के दोषी साबित होने पर अमेरिका में प्रवेश पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नई वीजा प्रतिबंध नीतियां उन व्यक्तियों और विदेशी सरकारों पर लागू होती हैं जो अवैध आव्रजन को बढ़ावा देते हैं।

ये चेतावनी या सलाह उन भारतीय नागरिकों के लिए लागू की गई है जो वर्क वीजा, छात्र वीजा, पर्यटक वीजा पर अमेरिका की यात्रा कर रहे है। इन सभी वीज़ा की अपनी अधिकृत प्रवास अवधि होती है। इस परामर्श का उद्देश्य विभिन्न गैर-आप्रवासी वीज़ा पर अमेरिका आने वाले यात्रियों को यह याद दिलाना है कि वे आव्रजन अधिकारियों द्वारा अमेरिका में प्रवेश के समय दी गई वैधता अवधि का कड़ाई से पालन करें। अमेरिकी दूतावास ने इस बात पर प्रकाश डाला कि थोड़े समय के लिए भी अधिक समय तक रुकने के गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

संक्षिप्त समाचार

गोवा में भारी बारिश, इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की

पणजी।

इंडिगो एयरलाइंस ने गोवा में भारी बारिश को देखकर अपने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में यात्रियों से कहा गया है कि वे अपने गंतव्य स्थल पर जाने से पहले अपनी फ्लाइट की जानकारी जरूर लें। एजवाइजरी में बताया गया हैं कि गोवा में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इस देखकर कई फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, वहीं कुछ फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है। एयरलाइंस ने कहा है कि हमारी टीम यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान करने में जुटी है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी यात्री को कोई समस्या न हो। हमारी टीम यात्रियों से लगातार संपर्क में बनी हुई है और उन्हें पल-पल की जानकारी दे रही है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी यात्री समय-समय पर अपने फ्लाइट्स की जानकारी लेते रहें। वे लगातार यह पता करते रहें कि कहीं उनके फ्लाइट्स की टाइमिंग में क्या बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा, सभी अतिरिक्त समय लेकर ही आगे कोई योजना बनाएं, ताकि उन्हें आगे चलकर कोई समस्या न हो। इंडिगो ने अपने सभी यात्रियों से सहयोग की अपील की है। बता दें कि गोवा में मंगलवार शाम से ही भारी बारिश का दौर जारी है। इसकारण फ्लाइट्स सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इससे यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जहां कुछ फ्लाइट्स के समय को बदल दिया गया है, वहीं कुछ को डायवर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने गोवा में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना को देखकर येलो अलर्ट जारी किया है।

गोलीबारी में मारे गए लोगों के घर के एक सदस्य को देंगे सरकारी नौकरी

जम्मू-कश्मीर के एलजी ने किया राजौरी-पुंछ का दौरा, लोगों से भी मिले

जम्मू।

जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि वे पहले राजौरी-पुंछ नहीं आ सके थे, लेकिन अब उन्होंने वहां के लोगों से मुलाकात की और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की और से की गई गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजन को मुआवजा दिया गया है और घायलों की हालत अब स्थिर है। सभी को प्रशासन की ओर से सहायता दी जा रही है। एलजी सिन्हा ने ऐलान किया कि जिन परिवारों ने अपने सदस्य खोए हैं, उनके घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कई घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई प्रशासन कर रहा है। पुनर्वास के लिए एक पैकेज केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सीमावर्ती इलाकों में बंकरों की जरूरत महसूस की जा रही है। जल्द ही नए बंकर बनाए जाएंगे ताकि लोग मुश्किल हालात में वहां सुरक्षित रह सकें।

पाकिस्तान की सरकार आंतकवाद को फंडिग करती है - संजय झा

नई दिल्ली।

पाकिस्तान के खिलाफ भारत के आतंकवाद विरोधी वैश्विक अभियान के तहत पहला प्रतिनिधिमंडल बुधवार को जापान रवाना होगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जदयू सांसद संजय झा ने इस बारे में बात की। उन्होंने डेलिगेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जाहिर किया। जदयू सांसद झा ने कहा दो बातें हैं। पहली, देश दशकों से आतंकवाद झेल रहा है। यह आतंकवाद हमेशा सीमा पार पाकिस्तान से आया है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। अतीत में, चाहे 2008 का मुंबई हमला हो या पुलवामा हमला, भारत ने हमेशा सारी जानकारी दुनिया के साथ साझा की। पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों को फंड करती है, सेना के जरिए प्रशिक्षण देती है, योजना बनाकर अंजाम देती है।उन्होंने कहा, यह भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी युद्ध की तरह है। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में साफ कह दिया है कि बहुत हो चुका। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें सारी जानकारी है। जदयू सांसद झा ने कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हैं कि वे सात डेलिगेशन भेज रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब से 'ऑपरेशन सिंदूर' हुआ है, सारे देश के लोग एकजुट होकर सरकार और सेना के साथ खड़े रहे हैं। सभी पार्टियों के लोग भी इस मुद्दे पर एक साथ हैं। इन सातों डेलिगेशन में सभी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। जब हम देश से बाहर जाते हैं, तब पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं।

कोर्ट ने कहा- कंपनी की हर गतिविधि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती

नेशनल हेराल्ड मामले में हुई सुनवाई, अब अगली सुनवाई जुलाई में

नई दिल्ली।

नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर आरोप-पत्र पर सुनवाई के दौरान ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा कि अनुसूचित अपराध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक ट्रिगर है और यह अपराध की गतिविधि हो सकती है, लेकिन कंपनी की हर गतिविधि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा कि क्या ये शेयर अनुसूचित अपराधों से उत्पन्न है? कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को कुछ चीजों को अपराध की आय के रूप में पहचानना होगा। कोर्ट ने पूछा क्या मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही के उद्देश्य के लिए शेयर, संपत्ति और किराए अपराध की आय बने रहेंगे? अदालत ने यह टिप्पणी और सवाल तब किए जब ईडी ने कहा कि यंग इंडियन के पास आरोपितों के लाभ के लिए जारी रखने के अलावा कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी। ईडी ने कहा शेयर, संपत्ति और किराया अपराध की आय है, जबकि विज्ञापन और ऋण को बाहर रखा गया। वहीं कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या आपके पास फोरेंसिक ऑडिटर है? कोर्ट को यह देखना होगा कि कंपनियां कैसे काम करती हैं और शेयर जारी करने के लिए क्या स्वीकार्य तरीके हैं। इसके जवाब में ईडी ने कहा कि यह केवल अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति से संबंधित हैं। एक बार शेयर जारी होने के बाद यह एक संपत्ति है। यंग इंडियन को एजेएल के शेयर जारी करना अपराध है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने 15 अप्रैल को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया था। कोर्ट इस मामले में 2 जुलाई से 8 जुलाई तक प्रतिदिन सुनवाई करेगी। मामले में ईडी के साथ अन्य आरोपितों की जिरह सुनी जाएगी। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब प्रतिवादियों ने रिकॉर्ड की जांच के लिए सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। हालांकि, ईडी ने इसका विरोध किया।

पहला कॉलम

जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

-ये मामला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास लंबित

नई दिल्ली।

कैश कांड में घिरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ये मामला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास लंबित है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। एफआईआर की मांग वाली याचिका वकील मैथ्यूज नेडुमपारा ने लगाई थी। दरअसल, जस्टिस वर्मा के घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। उनके घर के स्टोर रूम से 500-500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले थे। तब तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज के मुताबिक, 3 मई 2025 को तैयार की गई रिपोर्ट के साथ जस्टिस वर्मा का 6 मई का जवाब भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा गया है।

हरियाणा के यूट्यूबर पर क्यों मेहरबान हो रही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई

ज्योति, विकास श्योराण, ऋतु खोखर, पवन टोकस और नवांकुर शामिल

चंडीगढ़।

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा से अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सबसे चर्चित हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा है, जो ट्रैवल विद जो यूट्यूब चैनल चलाती थी। ज्योति पाकिस्तान के नेशनल डे पर वहां की एंबेसी में इफ्तार पार्टी में शामिल हुई थी। ज्योति ने अपने चैनल पर इसका वीडियो डाला था, जिसमें पाकिस्तान के वेलकम करने की खूब तारीफें की थीं। इन वीडियोज की वजह से ही वह सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आई। ज्योति के अलावा विकास श्योराण व उनकी पत्नी ऋतु खोखर के अलावा पवन टोकस व उनकी पत्नी ऋतु सांगवान और रोहतक के नवांकुर शामिल हैं। ये सभी पिछले एक-दो साल के दौरान पाकिस्तान घूमने गए हैं। खास बात यह है कि हर किसी ने अपने तरीके से पाकिस्तानी एंबेसी की तारीफ की है। विकास श्योराण ने कहा है कि हमने 5 दिन का वीजा मांगा था, हमें एक महीने का दिया गया। उधर, पाकिस्तान के साथ ज्योति का कनेक्शन सामने आने के बाद हरियाणा की नायाब सरकार अब पाकिस्तान का गुणगान करने वाले यूट्यूबरों पर सख्ती करने की तैयारी में है। इसके लिए बाकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) बनाया जाएगा। दरअसल नवांकुर यूट्यूब पर यात्री डॉक्टर के नाम से चैनल चलाते हैं। नवांकुर ने भी पाकिस्तान की यात्रा कर उसका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया था। वीडियो में वे ज्योति मल्होत्रा के साथ भी दिखाई दिए। इसी के बाद से वे पुलिस की रडार पर आ गए हैं। हालांकि, वे भारत में नहीं है, लेकिन वे अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर 2 बार इस बारे में सफाई दे चुके हैं।

ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में बोले अमित शाह- ऐसा पहली बार हुआ है

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ रुपये के इनामी समेत 27 नक्सलियों के मारे जाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 3 दशक में यह पहली बार है जब इतना बड़ा नक्सली नेता मारा गया है. गृह मंत्री ने कहा कि नम्बाला केशव राव उर्फ बसवराजू नक्सली आंदोलन का प्रमुख था. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है. छत्तीसगढ़ के नारायणपुर-बीजापुर-दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में बुधवार को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक प्रमुख नक्सली नेता बसवराजू समेत 27 नक्सलियों को मार गिराया.

गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता बताया. उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. गृह मंत्री ने कहा, ''नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में यह एक ऐतिहासिक सफलता है.'' आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने सीपीआई-माओवादी के सबसे बड़े नेता और नक्सली आंदोलन की जड़ नंबला केशव राव उर्फ बसवराजू सहित 27 खतरनाक माओवादियों को मार गिराया.

शाह ने आगे कहा, ÷नक्सलवाद के खिलाफ तीन दशक लंबे संघर्ष में यह पहली बार है कि सुरक्षा बलों ने महासचिव स्तर के किसी नेता को मार गिराया है.÷ मैं इस महान सफलता के लिए हमारे सुरक्षा बलों और एजेंसियों को बधाई देता हूं. गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 84 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है.

ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें बसव राजू भी शामिल था. बसव राजू को नंबल्ला केशव राव, कृष्णा, विनय, गंगन्ना, बसवराज, प्रकाश, विजय, केशव, बीआर, उमेश, राजू, दारापु नरसिम्हा रेड्डी और नरसिम्हा के नाम से भी जाना जाता था. वह आंध्र प्रदेश राज्य के जियानापेट, कोटाबोम्माली, श्रीकाकुलम के निवासी थे. वह 2018 से सीपीआई-माओवादी के महासचिव थे. वह केंद्रीय समिति के सदस्य भी थे. बसवराज दो एनआईए

मामलों में भी वांछित था. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2012 और 2019 में बसवराज के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थीं. 2019 की घटना में कथित तौर पर आईईडी विस्फोट में पांच सुरक्षाकर्मी मारे गए थे. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अबूझमाड़ इलाके में सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई. नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के माड़ प्रभाग में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) नारायणपुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर और डीआरजी कोंडागांव के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था.

नौसेना को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपना अहंकार त्याग दें और महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन दें

कोर्ट के आदेश के बावजूद स्थायी कमीशन नहीं मिला

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना को उसकी एक महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन नहीं देने के लिए जमकर फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने नेवी अधिकारियों से कहा, अब बहुत हुआ है, वे अपना अहंकार त्याग दें और अपने तौर-तरीके सुधारें।

दरअसल, जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच 2007 बैच की शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी सीमा चौधरी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें कोर्ट के आदेश के बावजूद स्थायी कमीशन नहीं मिला था।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अधिकारियों से पूछा कि क्या संबंधित अधिकारी सोचते हैं कि वे अदालत के आदेशों को दबा सकते हैं। आप किस तरह की अनुशासित फौज हैं। हम आपको महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन देने के लिए एक हफ्ता का समय देते हैं, गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले की जानकारी कोर्ट को दें।

दरअसल सीमा चौधरी को 6 अगस्त 2007 को भारतीय नौसेना की जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) ब्रांच में एसएससी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

उन्हें 2009 में लेफ्टिनेंट और 2012 में लेफ्टिनेंट कमांडर पद पर प्रमोट किया गया। 2016 और 2018 में दो-दो साल का सेवा विस्तार मिला था। 5 अगस्त 2020

को उन्हें बताया गया कि 5 अगस्त 2021 से उनकी सेवा समाप्त मानी जाएगी।

इस आदेश के खिलाफ सीमा सुप्रीम कोर्ट पहुंची, उन्होंने अपील की थी कि उन्हें स्थायी कमीशन नहीं मिला, जबकि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। 26 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सीमा चौधरी की रिव्यू याचिका पर फैसला देकर कहा था कि उनका मामला स्टैंडअलोन बेसिस पर देखा जाना चाहिए।

गोवा में दो दिन से जारी हैं भारी बारिश का दौर, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप

नई दिल्ली।

गोवा में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश जारी है। इसके चलते मौसम विभाग (आईएमडी) ने दोनों जिलों उत्तर और दक्षिण गोवा में बुधवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हीटवेव और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के लिए लखनऊ के अस्पतालों में कोल्ड वार्ड तैयार किए गए हैं। हीटवेब मरीजों के लिए 20 बेड रिजर्व हैं, जिसमें 10 इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से न निकलने की सलाह दी गई है। आईएमडी के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले चार-पांच दिनों में केरल पहुंच सकता है, जबकि पूर्वानुमान 27 मई का है। यदि ऐसा होता है तब 2009 के बाद से समय से पहले दस्तक देने वाला पहला मॉनसून होगा। 2009 में 23 मई को ही केरल में मॉनसून पहुंच गया था। विभाग के मुताबिक आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक देता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। यह 17 सितंबर के आसपास उत्तर-पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से हट जाता है।

अंबाला डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी

अंबाला।

हरियाणा के अंबाला डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद डीसी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह धमकी सुबह आधिकारिक ईमेल के द्वारा मिली थी। वहीं, पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। डीसी अंबाला ने बताया कि बुधवार सुबह डिप्टी कमिश्नर अंबाला के आधिकारिक ईमेल पर मेल आया जिसमें अंबाला के डीसी ऑफिस को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद डीसी की ओर से मामले में पुलिस को शिकायत दी गई। इस दौरान पुलिस टीम के साथ बम निरोधक दस्ता भी डीसी ऑफिस पहुंचा और जांच की। लेकिन उन्हें ऐसा कोई सामान नहीं मिला जिससे शक हो सके। डीसी ने बताया कि मामले में अब ईमेल पुलिस विभाग को उपलब्ध कराया गया है। अब वे जांच कर रहे हैं कि यह ईमेल कहां से आया और किसने भेजा। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने यह ईमेल देखा तो हमें लगा कि यह गलत है लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पर हमने इसकी जांच करवाई। जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अंबाला पुलिस जल्द ही ईमेल भेजने वाले को गिरफ्तार कर लेगी।

59 सांसदों की टीम 33 देशों में जाकर पाकिस्तान के आंतकी चेहरे को करेगी बेनकाब

पहला डेलिगेशन रवाना, दूसरा देर रात जाएगा

नई दिल्ली।

ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान का आंतकी चेहरा दुनिया को बताने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देश भेजा जा रहा है। 59 सांसद 7 सर्वदलीय टीमों (डेलिगेशन) में बंटे हैं। बुधवार को दो डेलिगेशन रवाना होने हैं, जिसमें कुल 17 सांसद हैं।

जेडीयू सांसद संजय झा की अगुआई वाला पहला डेलिगेशन विदेश रवाना हो गया है, जबकि शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला डेलिगेशन रात 9 बजे रवाना होगा। 7 टीमों के साथ 8 पूर्व राजनयिक भी शामिल है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने मंगलवार को सांसदों को इस पहल के बारे में ब्रीफिंग दी। सूत्रों के मुताबिक, इसमें ऑपरेशन सिंदूर का बैकग्राउंड और डिप्लोमैटिक एवं सैन्य कार्रवाई के पांच बड़े संदेश इन 33 देशों तक पहुंचाने पर जोर दिया। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस- सभी सांसदों को बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकी गुटों और उनके ढांचों के खिलाफ था। आतंकी अड्डों को नपी-तुली कार्रवाई में निशाना बनाया गया। पाक सेना ने आंतकी गुटों पर हुए हमले को खुद के खिलाफ हमला मानकर पलटवार किया।पाक आतंक का समर्थक इतना ही नहीं सभी सांसद कुछ सबूत लेकर जा रहे हैं, जिसमें वे बताएंगे कि पहलगाम हमले में पाक समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) की भूमिका थी। इसके पहले हुए हमलों का भी पूरा चिट्ठा सांसद ले जा रहे हैं।

भारत जिम्मेदार और संयमित = सांसदों को बताया गया हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सैन्य कार्रवाई में भी जिम्मेदारी और संयम का परिचय दिया। यह सुनिश्चित किया कि पाक के किसी निर्दोष नागरिक की जान न जाए। पाक ने कार्रवाई रोकने का जब आग्रह किया, तब भारत ने तत्परता से पाक का आग्रह स्वीकारा किया। आतंक के खिलाफ विश्व एकजुट सांसद देशों से आतंकवाद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने और इससे निपटने के लिए सहयोग व समर्थन भी मांग करने वाले है।

अपील होगी कि भारत-पाक के विवाद को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के तौर पर देखें। पाक को लेकर हमारी नीति सभी सांसद अपने दौरे के दौरान संबंधित देश को बताएंगे कि पाक के खिलाफ भारत ने अपना बदला हुआ दृष्टिकोण उजागर किया है। भारत सीमा पार से पैदा होने वाले खतरे को लेकर उदासीन रहने के बजाए प्रो- सक्रिय रवैया अपनाएगा और आतंकी हमलावरों को पहले ही निष्क्रिय करेगा।

बिहार में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित, आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत

पटना।

बिहार के कई जिलों में बुधवार को मौसम बदला। बेतिया, बगहा, मोतिहारी, रक्सौल और दरभंगा में सुबह-सुबह काले बादलों की वजह से अंधेरा छा गया। इसकारण लोगों को सड़कों पर गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा था। पटना, मधुबनी, बेतिया, औरंगाबाद, दरभंगा, मोतिहारी, रक्सौल और अररिया में बारिश हुई है। इस दौरान पूर्णिया और अररिया में आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। यहां आकाशीय बिजली भी गिरने की चेतावनी है। देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में हो रही बारिश का असर बिहार में भी दिख रहा है। बीते दो दिनों से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। इस दौरान 50 से 60 किमी की रफ्तार से हवा चल रही है। रक्सौल में भी हल्की बारिश हुई है। सुपौल में तेज बारिश के साथ आंधी भी चली। कई जगह पेड़ गिर गए। आकाशीय बिजली भी गिरी। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है।

आदिल, मूसा और अली से संपर्क में 2 या 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स, रोज रात में बदल रहे लोकेशन, हाइड आउट में छिपे

जांच एजेंसियों को नहीं मिल रही पुख्ता जानकारी

श्रीनगर।

पहलगाम हमले को महीना हो गया, सेना लगातार ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन आतंकियों को पकड़ नहीं सकी है। जांच में बस तीन नाम पता चले, आदिल, मूसा और अली। तीनों पर 20-20 लाख का इनाम रखा गया, 3 हजार से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, 113 लोग अरेस्ट किए गए, लेकिन आदिल, मूसा और अली का पता नहीं चला। उनकी लोकेशन तक ट्रेस नहीं हुई है। जांच एजेंसियों को इसकी दो वजह मान रही है। जांच एजेंसियों पहली वजह मान रही हैं कि आतंकी 2 या 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स के ही संपर्क में हैं, वहीं उन्हें जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। इससे आतंकियों को ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है। दूसरी वजह आतंकी जंगल, गुफाओं या पहाड़ी इलाकों में बने हाइड आउट में छिपे हैं, क्योंकि घरों में बने हाइड आउट की खबर लीक होने का खतरा होता है। जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड डीजीपी एसपी वैद्य, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख रहे ए.एस. दुलत और सुरक्षा एजेंसियों में अपने सूत्रों से बात की। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का मानना हैं कि आतंकी लगातार घने जंगल, पहाड़ों और गुफाओं में बने हाइड आउट में छिप रहे हैं। वे रात में लोकेशन बदल रहे हैं। आतंकियों की मदद सिर्फ 2 से 3 ओवर ग्राउंड वर्कर ही कर रहे हैं। ये उन आंतकियों के बेहद करीबी हैं। यही ओवर ग्राउंड वर्कर दूसरे नेटवर्क के द्वारा आतंकियों की मदद कर रहे हैं। आशंका है कि बायसरन घाटी में अटैक करने वाले आतंकी पिछले कई महीनों से कश्मीर में किसी से सीधे कॉन्टैक्ट में नहीं थे।

पाकिस्तान कर रहा दुनियां को गुमराह, बलूचिस्तान स्कूल बस विस्फोट के आरोपों को भारत ने किया खारिज

नई दिल्ली।

बलूचिस्तान के खुज़दार शहर में हुए दर्दनाक स्कूल बस विस्फोट को लेकर पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों को भारत सरकार ने सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद और राजनीति प्रेरित बताया है।

भारत ने साफ किया कि यह पाकिस्तान की एक और नाकाम कोशिश है दुनिया को गुमराह करने की।

इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस प्रकार के आरोप पाकिस्तान की उस रणनीति का हिस्सा हैं, जिसमें वह अपनी आतंरिक विफलताओं और आतंकवाद समर्थक छवि से ध्यान भटकाने के लिए भारत पर उंगली उठाता है।

दरअसल, बुधवार सुबह बलूचिस्तान के खुज़दार शहर में आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्रों को ले जा रही बस को एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी से टक्कर मार दी थी, जिससे जोरदार धमाका हुआ।

इस हमले में पांच लोगों की जान चली गई, जिनमें तीन बच्चे शामिल थे, जबकि कई अन्य घायल हो गए।

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत खुज़दार में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे को लेकर पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को सिरे से खारिज करता है। भारत इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। लेकिन पाकिस्तान की यह आदत बन चुकी है कि वह अपनी आतंकवाद समर्थक नीति और आंतरिक अव्यवस्थाओं से ध्यान हटाने के लिए बार-बार भारत पर झूठे आरोप लगाता है। उन्होंने आगे कहा, कि दुनिया को गुमराह करने का यह प्रयास पहले की तरह इस बार भी नाकाम होगा।

पाकिस्तान ने कहा- भारत की संलिप्तता की जांच चल रही

गौरतलब है कि पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि इस हमले में किसी विदेशी हाथ विशेषकर भारत की कथित संलिप्तता की जांच की जा रही है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत पर इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। भारत पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि वह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है।

उधर, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान पर बार-बार यह आरोप लगता रहा है कि वह सीमा पार आतंकवाद को संरक्षण देता है और आतंकी संगठनों को अपने राज्यतंत्र से समर्थन प्रदान करता है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमाआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717